रणजीत टाइम्स

इंदौर

शुक्रवार, 19 जून, 2026

वर्ष 02 | अंक 148 कुल पृष्ठ : 8 | Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

डोनाल्ड ट्रंप ने लिया ईरान की जब्त संपत्ति छोड़ने का फैसला, कहा -'हमारा पैसा नहीं'

वॉशिंगटन/जिनेवा। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump और ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने एक शांति समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच टकराव समाप्त करना, क्षेत्रीय स्थिरता बढ़ाना और आगे की वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त करना है। समझौते के तहत ईरान को आर्थिक राहत देने, तेल निर्यात पर कुछ प्रतिबंधों में ढील देने और चरणबद्ध तरीके से जमी हुई (फ्रोजन) ईरानी संपत्तियों तक पहुंच बहाल करने का प्रावधान शामिल है। हालांकि इन परिसंपत्तियों की रिहाई समझौते की शर्तों के पालन और आगे की वार्ताओं की प्रगति से जुड़ी बताई गई है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मुद्दे पर कहा कि ये धनराशि मूल रूप से ईरान की है और अमेरिका उसका मालिक नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को कोई नया वित्तीय अनुदान नहीं दे रहा, बल्कि समझौते के तहत कुछ जमी हुई संपत्तियों और आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़े मुद्दों पर समाधान तलाशा जा रहा है। समझौते में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला रखने, क्षेत्रीय तनाव कम करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर आगे की बातचीत जारी रखने पर भी सहमति बनी है।

हालांकि इस समझौते को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। आलोचकों का कहना है कि ईरान को आर्थिक रियायतें देने से पहले उसकी प्रतिबद्धताओं का पूर्ण सत्यापन होना चाहिए, जबकि समर्थकों का तर्क है कि यह समझौता पश्चिम एशिया में स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम है।

फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत

पेरिस। प्रधानमंत्री अपने आधिकारिक दौरे पर फ्रांस की राजधानी पहुंच गए। पेरिस पहुंचने पर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एकत्र हुए और "भारत माता की जय" तथा "मोदी-मोदी" के नारों से माहौल गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों का अभिवादन स्वीकार किया और उनसे आत्मीय संवाद भी किया। कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं तथा भारत की उपलब्धियों और वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिष्ठा को लेकर खुशी जताई।

फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति से होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों, रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित ऊर्जा, निवेश और व्यापार सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रतिष्ठित VivaTech-2026 सम्मेलन में भी भाग लेंगे, जहां दुनिया भर के तकनीकी विशेषज्ञ, स्टार्टअप उद्यमी और निवेशक जुटेंगे। सम्मेलन में भारत की डिजिटल प्रगति, नवाचार क्षमता और तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह यात्रा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के साथ-साथ तकनीक, रक्षा और आर्थिक सहयोग के नए अवसर भी पैदा करेगी। हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और फ्रांस भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है।

प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवाटेक-2026 सम्मेलन में भाग लेंगे

पेरिस/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिष्ठित VivaTech-2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप, नवाचार और प्रौद्योगिकी सम्मेलन माना जाता है, जहां दुनिया भर के उद्यमी, निवेशक, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति-निर्माता जुटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों सम्मेलन में नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और उभरती तकनीकों पर विचार साझा करेंगे। दोनों नेता भारत और फ्रांस के बीच तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने के साथ-साथ युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने पर भी जोर देंगे। भारत पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। देश में 1.5 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप

कार्यरत हैं और यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में वीवाटेक-2026 सम्मेलन भारत के तकनीकी कौशल और नवाचार क्षमता को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। सम्मेलन के दौरान भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच निवेश, अनुसंधान एवं विकास (R&D), सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की संयुक्त उपस्थिति भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच तकनीक, निवेश और नवाचार के क्षेत्र में नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

मुख्य बिंदु-प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों वीवाटेक-2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। AI, स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक और हरित नवाचार पर विशेष फोकस रहेगा। भारत-फ्रांस तकनीकी और आर्थिक सहयोग को नई गति मिलने की उम्मीद। भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर दोनों देशों का जोर।

हर 35 मिनट में एक ट्रेड!

ट्रंप के निवेश खाते में 3 महीने में 3642 सौदे, अमेरिका में मचा राजनीतिक तूफान

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। इस बार मामला उनके निवेश खाते से जुड़ी कथित शेयर ट्रेडिंग गतिविधियों का है। सामने आई जानकारी के अनुसार पिछले तीन महीनों में ट्रंप से जुड़े निवेश खाते से 3,642 बार शेयरों की खरीद-बिक्री की गई। आंकड़ों के मुताबिक यह औसतन हर 35 मिनट में एक ट्रेड के बराबर है, जिसने अमेरिका में राजनीतिक और वित्तीय बहस छेड़ दी है। विपक्षी डेमोक्रेट नेताओं ने इस असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि कहीं इसमें संवेदनशील सरकारी सूचनाओं का लाभ तो नहीं लिया गया। कई विपक्षी सांसदों ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है और इसे संभावित 'इनसाइडर ट्रेडिंग' से जोड़कर देखा है। हालांकि Trump Organization ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन का कहना है कि संबंधित निवेश गतिविधियां पेशेवर वित्तीय प्रबंधकों द्वारा संचालित की जाती हैं और राष्ट्रपति ट्रंप का व्यक्तिगत रूप से इन सौदों के संचालन में कोई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। कंपनी के अनुसार सभी निवेश गतिविधियां लागू कानूनों और वित्तीय नियमों के अनुरूप की गई हैं। मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ा है क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति और उच्च पदस्थ अधिकारियों के वित्तीय हितों को लेकर पहले से ही पारदर्शिता की मांग उठती रही है। आलोचकों का कहना है कि यदि किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े खाते में इतनी बड़ी संख्या में लेनदेन हो रहे हैं तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि इन फैसलों के पीछे कौन है और क्या हितों के टकराव की कोई संभावना है। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े निवेश फंड और पोर्टफोलियो में एल्गोरिदम आधारित ट्रेडिंग या सक्रिय निवेश प्रबंधन के कारण बड़ी संख्या में सौदे होना असामान्य नहीं माना जाता।

'ऑपरेशन टाइगर' पर मंडराया संकट!

स्पीकर को भेजे पत्र पर उद्धव गुट के 2 सांसदों के हस्ताक्षर नहीं, बदल सकते हैं सियासी समीकरण

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर नया मोड़ सामने आया है। शिवसेना के शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान के बीच लोकसभा अध्यक्ष को भेजे गए एक पत्र में उद्धव गुट के दो सांसदों के हस्ताक्षर नहीं होने की खबर ने सियासी अटकलों को और तेज कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना (यूबीटी) खेमे की ओर से सांसदों के समर्थन को लेकर जो पत्र भेजा गया था, उसमें दो सांसदों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पार्टी के भीतर कोई असहमति है या फिर कुछ सांसद अलग राजनीतिक रुख अपनाने की तैयारी में हैं।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री रह चुके के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने दावा किया है कि उनका 'ऑपरेशन टाइगर' सफल हो रहा है और कई नेता तथा जनप्रतिनिधि उनके संपर्क में हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे खेमे ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा है कि पार्टी एकजुट है और विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि हस्ताक्षरों को लेकर उठे सवालों का जल्द समाधान नहीं हुआ, तो इससे विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों को नए राजनीतिक हथियार मिल सकते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि हस्ताक्षर नहीं होने के पीछे तकनीकी कारण हैं या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है। इस बीच दोनों गुट अपने-अपने विधायकों और सांसदों को एकजुट रखने में जुटे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में हुए घटनाक्रमों को देखते हुए हर छोटा घटनाक्रम भी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित सांसद इस मामले पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं और आने वाले दिनों में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर कौन-सा नया राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है।

संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने 13 क्षेत्रों में भुखमरी की स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी दी

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और मानवीय सहायता एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि दुनिया के 13 संवेदनशील क्षेत्रों में आने वाले महीनों में भुखमरी और खाद्य संकट की स्थिति और गंभीर हो सकती है।

संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय सहायता में कमी के कारण लाखों लोगों के सामने भोजन का संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के अनुसार, कई देशों और क्षेत्रों में लोग पहले से ही अत्यधिक खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यदि तत्काल मानवीय सहायता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग नहीं बढ़ाया गया तो बड़ी संख्या में लोगों को अकाल जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट में विशेष रूप से युद्ध और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। सशस्त्र संघर्षों के कारण कृषि गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाओं ने भी खाद्य उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि खाद्य सहायता कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहयोग बढ़ाया जाए, ताकि संकटग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री और आवश्यक खाद्य आपूर्ति पहुंचाई जा सके। एजेंसियों ने चेतावनी दी कि सहायता में देरी या कमी से मानवीय संकट और गहरा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा केवल मानवीय मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। भुखमरी और कुपोषण बढ़ने से विस्थापन, अस्थिरता और संघर्ष की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं।

सियासी गलियारों में नई हलचलः सपा में टूट की अटकलें तेज, 25-27 सांसदों के संपर्क में होने के दावे पर मचा घमासान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दल-बदल और राजनीतिक पुनर्संरेखण की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) और शिवसेना से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बाद अब समाजवादी पार्टी (सपा) को लेकर भी टूट की अटकलें सामने आ रही हैं।

राजनीतिक गलियारों में दावा किया जा रहा है कि सपा के 25 से 27 सांसद पार्टी नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और अलग राह चुन सकते हैं। हालांकि, ने इन दावों को पूरी तरह निराधार और राजनीतिक अफवाह करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सपा पूरी तरह एकजुट है और विपक्षी दल जानबूझकर भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

सूत्रों के हवाले से चल रही चर्चाओं में कहा जा रहा है कि कुछ सांसदों की नाराजगी को लेकर लगातार राजनीतिक संपर्क बनाए जा रहे हैं। हालांकि अब तक किसी सांसद ने सार्वजनिक रूप से पार्टी छोड़ने या असंतोष जताने की पुष्टि नहीं की है। ऐसे में इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। सपा ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं। पार्टी का कहना है कि सांसदों और संगठन के बीच नियमित संवाद चल रहा है तथा किसी प्रकार के विभाजन का सवाल ही नहीं उठता। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच विभिन्न दलों में टूट-फूट की अटकलें लगना असामान्य नहीं है। लेकिन जब तक कोई सांसद या विधायक आधिकारिक रूप से अपना रुख स्पष्ट नहीं करता, तब तक ऐसे दावों को राजनीतिक अटकलों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। फिलहाल सपा नेतृत्व स्थिति पर नजर बनाए हुए है, जबकि राजनीतिक विरोधी दल इन चर्चाओं को हवा देने में जुटे हैं। आने वाले दिनों में यदि कोई ठोस घटनाक्रम सामने आता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं।

चाय की दुकान खोलूं या आलू बड़ा बेचूं...

राजेश धाकड़

सोच रहा हूं पत्रकारिता छोड़कर कोई धंधा कर लूं। चाय की दुकान खोलूं या आलू बड़ा बेचूं। कम से कम वहां मेहनत का हिसाब तो साफ रहेगा। सुबह आलू उबालो, दोपहर तक बड़े तलो, शाम को पैसे गिनो और रात को चैन की नींद सो जाओ। यहां पत्रकारिता में सुबह खबर ढूंढो, दिनभर फोन घुमाओ, शाम को खबर लिखो और रात को यह सोचते हुए सो जाओ कि आखिर मिला क्या?

पत्रकारिता का हाल अब ऐसा हो गया है कि बच्चों को मैलोडी दिलाने के लिए भी जेब टटोलनी पड़ती है। झालमुड़ी खाने का मन करे तो पहले बैंक बैलेंस देखना पड़ता है। कभी-कभी तो लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा कमजोर हालत पत्रकारों की अर्थव्यवस्था की है। फर्क सिर्फ इतना है कि देश का बजट संसद में पेश होता है और पत्रकार का घाटा उसकी जेब में। आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी दिलचस्प चीज हो गई हैं। पहले पत्रकार खबर लेने जाता था, अब प्रवेश लेने जाता है। अगर गलती से काले कपड़े पहनकर पहुंच गए

तो सुरक्षा कर्मी ऐसे घूरते हैं जैसे आप सवाल पूछने नहीं, सरकार गिराने आए हों। यदि कोई पत्रकार हिम्मत करके जनता के सवाल पूछ ले तो जवाब मिलता है—"आज का विषय यह नहीं है।" यानी जनता की समस्या अगर निर्धारित विषय नहीं है, तो जनता भी निर्धारित महत्व की नहीं है।

राजनीति में भी बड़ा बदलाव आया है। कभी संगठन सर्वोपरि हुआ करता था। कार्यकर्ता पार्टी का नाम लेकर गर्व महसूस करता था। नेता कहते थे कि संगठन बड़ा है, व्यक्ति छोटा। लेकिन आज कई जगह दृश्य कुछ उल्टा दिखाई देता है। संगठन पीछे खड़ा दिखाई देता है और व्यक्ति सबसे आगे। ऐसे समय में बार-बार याद आते हैं । वह अटल जो राजनीति में मर्यादा का पर्याय थे। वह अटल जो विरोधियों का सम्मान करते थे। वह अटल जिनके पास करोड़ों का वैभव नहीं था लेकिन करोड़ों लोगों का सम्मान था। उन्होंने राजनीति को संवाद दिया, लोकतंत्र को असहमति का अधिकार दिया और सवालों को लोकतंत्र की ताकत बताया। लेकिन आज हालात देखकर कभी-कभी लगता है कि अटल की राजनीति और आज की राजनीति के बीच वर्षों का नहीं, सदियों का अंतर आ गया है।

सत्ता का सुख भी बड़ा विचित्र होता है। यह आदमी को इतना ऊंचा उठा देता है कि उसे नीचे खड़ी जनता दिखाई देना बंद हो जाती है। उसे लगता है कि तालियां हमेशा बजती रहेंगी, जयकारे हमेशा लगते रहेंगे और इतिहास हमेशा उसकी प्रशंसा करता रहेगा। लेकिन इतिहास बड़ा निर्मम होता है। वह केवल कर्मों का हिसाब रखता है। जो लोग आज आलोचना से डरते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र में सवाल दुश्मनी नहीं होते। सवाल लोकतंत्र का स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं। जिस दिन सवाल पूछने वाले खत्म हो जाएंगे, उसी दिन लोकतंत्र का बुखार बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी चाय की दुकान खोलने का फैसला टाल दिया है। आलू बड़ा भी अभी नहीं बेचेंगे। क्योंकि अगर सारे पत्रकार चाय बेचने लगेंगे तो सत्ता से सवाल कौन पूछेगा? अगर सभी कलम छोड़कर कढ़ाई पकड़ लेंगे तो जनता की आवाज कौन बनेगा?

हां, पत्रकारिता अब पहले जैसी नहीं रही। सम्मान कम हुआ है, संघर्ष बढ़ा है, आय घटी है और अपेक्षाएं बढ़ी हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सत्ता से बड़ी कोई चीज है तो वह जनता है, और जनता की आवाज से बड़ा कोई हथियार है तो वह एक ईमानदार पत्रकार की कलम। जब तक सवाल जिंदा हैं, तब तक पत्रकारिता भी जिंदा है। और जिस दिन सवाल मर गए, उस दिन लोकतंत्र केवल एक सरकारी पोस्टर बनकर रह जाएगा।

मानसून में ऑयली स्किन करती है ज्यादा परेशान? चेहरे पर लगाएं ये चीजें, आएगा निखार

लाइफस्टाइल डेस्क। मानसून का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं ऑयली स्किन वालों के लिए कई नई परेशानियां भी लेकर आता है। हवा में बढ़ी नमी के कारण त्वचा अधिक तेल (सीबम) बनाने लगती है, जिससे चेहरा चिपचिपा दिखाई देता है। इसके साथ ही धूल, पसीना और बैक्टीरिया मिलकर मुंहासों, ब्लैकहेड्स और त्वचा संबंधी अन्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी त्वचा भी मानसून में जरूरत से ज्यादा ऑयली हो जाती है, तो कुछ प्राकृतिक और त्वचा के अनुकूल चीजों का इस्तेमाल करके आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं।

1. एलोवेरा जेल-एलोवेरा त्वचा को ठंडक पहुंचाने के साथ अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों की समस्या को भी कम कर सकते हैं। रात में सोने से पहले चेहरे पर शुद्ध एलोवेरा जेल लगाना फायदेमंद हो सकता है।

2. मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक-मुल्तानी मिट्टी त्वचा से अतिरिक्त तेल और गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। सप्ताह में एक या दो बार गुलाब जल के साथ इसका फेस पैक लगाने से त्वचा ताजा और साफ महसूस होती है।

3. गुलाब जल-गुलाब जल एक प्राकृतिक टोनर की तरह काम करता है। यह त्वचा के पीएच स्तर को संतुलित रखने और चेहरे को तरोताजा बनाए रखने में मदद करता है। दिन में दो से तीन बार कॉटन की मदद से गुलाब जल लगाया जा सकता है।

4. खीरे का रस-खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो त्वचा को हाइड्रेट रखने के साथ अतिरिक्त तेल कम करने में मदद करती है। खीरे का रस चेहरे पर लगाने से त्वचा को ठंडक और ताजगी मिलती है।

5. नीम का फेस पैक-नीम में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मुंहासों और त्वचा संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं। नीम पाउडर या नीम के पत्तों का पेस्ट सप्ताह में एक बार लगाया जा सकता है।

इन बातों का भी रखें ध्यान दिन में दो बार माइल्ड फेसवॉश से चेहरा साफ करें।

दिल्ली की हवा बना रही त्वचा को समय से पहले बूढ़ा! प्रदूषण, हार्ड वाटर और धूप से बढ़ा खतरा

Delhi। देश की राजधानी दिल्ली अब सिर्फ प्रदूषण के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि दिल्ली के लोगों की त्वचा समय से पहले बूढ़ी हो रही है।

विशेषज्ञों के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण लगातार बढ़ता प्रदूषण, कठोर पानी (हार्ड वाटर) और तेज़ अल्ट्रावायलेट (UV) किरणों के लंबे समय तक संपर्क में रहना है। यह अध्ययन Ningen Skin Sciences ने Ariga Research के सहयोग से किया है। इसे देश के सबसे बड़े एआई आधारित स्किन स्टडीज में से एक माना जा रहा है। इस रिसर्च में भारत के 725 शहरों के 21,373 लोगों की त्वचा का विश्लेषण किया गया, ताकि अलग-अलग शहरों में त्वचा के स्वास्थ्य और उसके पैटर्न को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अध्ययन में शोधकर्ताओं ने स्किनसेंसएआई प्लेटफॉर्म के जरिए एआई आधारित फेस स्कैन का उपयोग किया। इस तकनीक की मदद से त्वचा के 12 अलग-अलग स्वास्थ्य मानकों का मूल्यांकन किया गया। इनमें झुर्रियां, काले घेरे, त्वचा की कसावट, लचीलापन, निर्जलीकरण और रंगद्रव्य जैसी समस्याएं शामिल थीं। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दिल्ली ने त्वचा की कसावट में गिरावट का सबसे खराब स्कोर दर्ज किया। राजधानी का स्कोर 5 में से 4.11 रहा, जो राष्ट्रीय औसत 3.62 से करीब 18 प्रतिशत अधिक है। इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली के लोगों की त्वचा पर उम्र बढ़ने के संकेत सामान्य से पहले दिखाई दे रहे हैं। तुलना करें तो Kolkata का स्कोर 3.49 रहा, जो दिल्ली से बेहतर स्थिति को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली की खराब हवा में मौजूद धूल, धुआं और जहरीले कण त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे त्वचा की प्राकृतिक नमी कम होती है और कोलेजन तेजी से टूटने लगता है। यही कारण है कि त्वचा की कसावट घटती है और झुर्रियां जल्दी दिखने लगती हैं। इसके अलावा दिल्ली में हार्ड वाटर भी एक बड़ा कारण माना गया है। कठोर पानी में मौजूद मिनरल्स त्वचा को रूखा बना देते हैं और उसकी प्राकृतिक सुरक्षा परत को कमजोर कर सकते हैं। वहीं तेज धूप और UV किरणों के लगातार संपर्क से स्किन पिग्मेंटेशन, टैनिंग और फाइन लाइंस की समस्या बढ़ती है। त्वचा विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्थिति से बचने के लिए लोगों को अपनी स्किन केयर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। रोजाना सनस्क्रीन का उपयोग, चेहरे की नियमित सफाई, पर्याप्त पानी पीना और एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन लेना त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। साथ ही प्रदूषण से बचाव के लिए चेहरे को ढककर निकलना और घर लौटने के बाद स्किन को अच्छी तरह साफ करना भी जरूरी है। यह अध्ययन साफ संकेत देता है कि महानगरों की तेज रफ्तार जिंदगी और बिगड़ता पर्यावरण अब सिर्फ फेफड़ों या दिल के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है।

करेरा को मिला आध्यात्मिक सौभाग्य : बागेश्वर पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भोला महाराज के आग्रह पर श्रीमद्भागवत कथा के लिए दी स्वीकृति

हेमंत भार्गव

करेरा। करेरा की पावन धरा एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना और भक्ति रस में सराबोर होने जा रही है। विश्व विख्यात कथावाचक एवं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ब्राह्मण समाज अध्यक्ष एवं कथा यजमान पंडित श्री राजेश दुबे "भोला महाराज" के विशेष आग्रह को स्वीकार करते हुए 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक करेरा में श्रीमद्भागवत कथा करने की स्वीकृति प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि लगभग एक वर्ष पूर्व शिवपुरी प्रवास के दौरान बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने मंच से घोषणा करते हुए करेरा में पुनः आगमन एवं कथा करने का आश्वासन दिया था। यद्यपि उस समय तिथियां निर्धारित नहीं की

गई थीं, किन्तु हाल ही में जारी उनके अधिकृत कथा कार्यक्रम में करेरा का नाम सम्मिलित होने से क्षेत्रवासियों में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण व्याप्त हो गया है।

कथा यजमान पंडित श्री राजेश दुबे "भोला महाराज" ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह करेरा क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है कि देश-विदेश में अपनी ओजस्वी वाणी और सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए विख्यात पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर क्षेत्रवासियों को अपने सान्निध्य एवं आशीर्वाद का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि कथा आयोजन के लिए उपयुक्त स्थल का चयन शीघ्र किया जाएगा। यदि सभी व्यवस्थाएं अनुकूल रहीं तो यह भव्य आयोजन कृषि उपज मंडी प्रांगण में संपन्न कराया जाएगा। आस्था, भक्ति और सनातन संस्कृति के इस महापर्व को लेकर करेरा सहित आसपास के क्षेत्रों में अभी से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दौरान हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

गुड़र ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा बढ़कर 3, पिता ने भी तोड़ा दम

अतुल जैन

(मासूम बेटी और पड़ोसी बालक की मौत के बाद प्राण सिंह ने भी इलाज के दौरान गंवाई जिंदगी)

(डीजल-पेट्रोल और गैस सिलेंडर दोनों एंगल पर जांच जारी)

खनियाधाना। थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़र में बुधवार सुबह हुए भीषण विस्फोट और अग्निकांड ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। गुरुवार शाम करीब 4:30 बजे गंभीर रूप से झुलसे मकान मालिक प्राण सिंह प्रजापति ने ग्वालियर स्थित जयारोग्य अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले उनकी 4 वर्षीय पुत्री जानवी प्रजापति और पड़ोस के 11 वर्षीय बालक कल्ला आदिवासी की भी मौत हो चुकी है।

(एक परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़)-हादसे की पहली शिकार 4 वर्षीय मासूम जानवी बनी, जिसकी बुधवार को मलबे में दबने से मौके पर ही मौत हो गई थी। गुरुवार सुबह उपचार के दौरान कल्ला आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। वहीं शाम को प्राण सिंह की मौत की खबर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। एक ही हादसे में पिता, पुत्री और पड़ोस के बच्चे की मौत ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है।

(नाश्ता बनाते समय हुआ था भीषण विस्फोट)-जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह प्राण सिंह के घर में रोजमर्रा की तरह रसोई में नाश्ता तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा

मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि छत और दीवारें भरभराकर गिर गईं तथा कुछ ही क्षणों में आग की लपटों और धुएं ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाका किसी बम विस्फोट जैसा महसूस हुआ। तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया। बाद में पुलिस, प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य चलाया।

(पत्नी और पुत्र अब भी जिंदगी से जूझ रहे)-हादसे में प्राण सिंह की पत्नी रोशनी प्रजापति तथा पुत्र शिवा प्रजापति गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों का उपचार ग्वालियर में जारी है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।

(ब्लास्ट की असली वजह बनी रहस्य)-विस्फोट के कारणों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि घर में रखा डीजल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ आग की चपेट में आ गया, जिससे हादसा विकराल रूप ले बैठा। वहीं गैस सिलेंडर में रिसाव की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मलबे से साक्ष्य जुटाकर मामले की गहन जांच कर रही है।

(कलेक्टर, एसपी और विधायक पहुंचे मौके पर)-घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा, पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया तथा क्षेत्रीय विधायक प्रीतम लोधी तत्काल गुड़र गांव पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। प्रशासन द्वारा घायलों के उपचार की समुचित व्यवस्था कराई गई है।

(गांव में पसरा मातम)-दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गुड़र गांव में शोक का माहौल है। कई घरों में चूल्हे नहीं जले और ग्रामीणों की आंखें नम हैं। हर कोई यही कह रहा है कि एक पल में हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे इस भीषण विस्फोट की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

अकेलेपन के अवसाद को दूर करता है सहजयोग का सामूहिकता का सिद्धांत

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्यों के साथ, मनुष्यों के बीच रहकर ही वो सामान्य जीवन जी सकता है। अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है, जिससे वो डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारी से ग्रसित होने लगता है। इंसान किसी न किसी कारण से ही समाज से दूर होने लगता है जैसे- किसी से गहरा आघात पाना, किसी प्रयास में असफल होना, पारिवारिक अशांति, आर्थिक या शारीरिक तकलीफ इत्यादि मनुष्य को अकेलेपन का शिकार बना देता है। निराशाजनक स्थिति में जब मनुष्य खालीपन अनुभव करता है तब कुछ दिनों तक उसे वह खालीपन अच्छा लगता है क्योंकि उसे लोगों का सामना नहीं करना होता, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना पड़ता है।

पर, धीरे धीरे यही खालीपन की स्थिति उसे गहन अंधकार में ढकेलने लगती है। यह स्थिति इतनी धीरे-धीरे आती है कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता। अपने परिवार समाज में लोगों से मिलजुल कर जब हम अपनी समस्या या दुख किसी से बांटते हैं, तब भले ही हमें उनकी सहायता ना मिले पर अपने मन की बात किसी के सामने रखकर हम अपनी पीड़ा से थोड़ी सी राहत तो पा ही लेते हैं। और.. जहाँ तक मदद की बात है हमसे ज्यादा हमारी मदद कोई और नहीं कर सकता है। सहज ध्यान योग में सामूहिकता का सबसे ज्यादा महत्व है। सहज योग पद्धति से जब हम ध्यानावस्था में होते हैं तब कुंडलिनी जागरण से हमारे अंदर प्रवाहित होने वाले चैतन्य, हमारे साथ बैठे साधकों के चैतन्य से मिल जाता है और उसका प्रभाव दुगुना हो जाता है। ईश्वर से एकाकारिता इस चैतन्य को इतनी शक्तिशाली बना देती है कि यदि साथ बैठे साधकों में यदि नकारात्मकता होगी तो धीरे धीरे वह उस नकारात्मकता से मुक्ति पा लेगा। यही वो कारण है जिसके कारण सहज योग में सामूहिकता की अनिवार्यता है। और जैसे कि पहले ही कहा गया है कि स्वयं की मदद सिर्फ हम ही कर सकते हैं।

किसी भी स्थिति में नकारात्मकता को अंगीकार कर अकेलेपन को स्वीकार नहीं करना है। ध्यान योग सीखकर, ध्यान मे बैठकर, स्वयं की स्थिति को स्वयं समझना और सकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को जोड़ने का प्रयास सभी को करना चाहिए क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। अतः चलिए सहज योग से जुड़ते हैं और अपने अंदर के सद्गुणों को पहचान कर, ईश्वर ने जो सुंदर जीवन दिया है, उसकी कद्र करते हुए शांतिपूर्ण, खुशहाल जीवन जीने के लिये स्वयं पहल करते हैं। सहज योग के बारे में जानकारी हमारे टोल फ्री नंबर 18002700800 अथवा www.sahajayoga.org.in से प्राप्त सकते हैं ।

ऑटिज्म बीमारी नहीं, समझ की जरूरतः बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर माता-पिता को जाननी चाहिए अहम बातें

नई दिल्ली। हर साल 18 जून को मनाया जाने वाला Autistic Pride Day समाज को यह याद दिलाता है कि ऑटिज्म किसी कमी या बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि यह दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है।

इसके बावजूद आज भी समाज में ऑटिज्म को लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। इन्हीं भ्रमों की वजह से कई बार बच्चों की सही समय पर पहचान नहीं हो पाती और जरूरी मदद मिलने में देरी हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटिज्म को "ठीक" करने की सोच ही गलत है। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज करके खत्म किया जा सके। यह एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है, जो ज्यादातर आनुवंशिक कारणों से जुड़ी होती है। सही समय पर पहचान, समझ और सही सपोर्ट के जरिए ऑटिस्टिक बच्चों को बेहतर जीवन दिया जा सकता है।

विशेषज्ञों के अनुसार, माता-पिता को ऑटिज्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म के संकेत बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। आमतौर पर दो साल की उम्र से पहले ही इसके शुरुआती लक्षण नजर आने लगते हैं। कई मामलों में जन्म से लेकर 12 महीने की उम्र के बीच ही बच्चे के व्यवहार में अंतर दिखाई देने लगता है। जैसे आंखों में कम संपर्क बनाना, नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना, इशारों का कम इस्तेमाल करना या सामाजिक जुड़ाव में कमी होना। अक्सर परिवार इसे "देर से बोलने वाला बच्चा" मानकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन यही देरी बाद में चुनौती बन सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 18 महीने की उम्र तक ऑटिज्म की पहचान संभव है।

दूसरी बात यह समझना जरूरी है कि Autism Spectrum Disorder एक "स्पेक्ट्रम" है। इसका मतलब है कि हर बच्चा अलग होता है और उसके लक्षण भी अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, जबकि कुछ सामान्य रूप से बात कर सकते हैं लेकिन सामाजिक संकेतों को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए किसी एक बच्चे के अनुभव के आधार पर सभी बच्चों को नहीं समझा जा सकता।

तीसरी बड़ी बात यह है कि ऑटिज्म का कारण परवरिश या वैक्सीन नहीं है। लंबे समय से समाज में यह गलत धारणा फैली रही है कि बच्चों को लगने वाले टीके ऑटिज्म का कारण बनते हैं, लेकिन वैज्ञानिक शोध इसे पूरी तरह गलत साबित कर चुके हैं। ऑटिज्म मुख्य रूप से जेनेटिक और न्यूरोलॉजिकल कारणों से जुड़ा होता है। माता-पिता को इस तरह की अफवाहों से बचना चाहिए।

चौथी बात यह है कि जल्दी हस्तक्षेप (Early Intervention) बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि बच्चे में शुरुआती लक्षण दिखें तो तुरंत विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे उपाय बच्चे के विकास में बड़ा फर्क ला सकते हैं। जितनी जल्दी सपोर्ट शुरू होता है, बच्चे के सीखने और सामाजिक विकास की संभावना उतनी बेहतर होती है। पांचवीं और सबसे अहम बात यह है कि ऑटिस्टिक बच्चों को बदलने की नहीं, समझने और स्वीकारने की जरूरत होती है। हर बच्चा अपनी क्षमता और तरीके से सीखता है। परिवार और समाज का सहयोग उनके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यदि उन्हें लगातार दबाव में रखा जाए या उनकी तुलना दूसरे बच्चों से की जाए, तो इससे उनकी भावनात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटिज्म कोई कमजोरी नहीं है। दुनिया में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने ऑटिज्म के साथ असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं।

PPF में गलती पड़ सकती है भारी! एक से ज्यादा अकाउंट खोले तो फंस सकता है पैसा, ब्याज भी हो सकता है जब्त

नई दिल्ली। सुरक्षित निवेश और टैक्स बचत के लिए देशभर में करोड़ों लोग Public Provident Fund यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को सबसे भरोसेमंद विकल्प मानते हैं। लंबी अवधि के निवेश, गारंटीड रिटर्न और टैक्स फ्री ब्याज की वजह से यह स्कीम मध्यम वर्ग से लेकर बड़े निवेशकों तक के बीच काफी लोकप्रिय है। लेकिन इसी स्कीम को लेकर कई लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है।

अक्सर देखा जाता है कि कुछ निवेशक अलग-अलग बैंकों या पोस्ट ऑफिस में एक से ज्यादा PPF अकाउंट खुलवा लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वे सालाना तय सीमा से ज्यादा पैसा जमा कर सकेंगे और अधिक ब्याज का फायदा मिलेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। नियम साफ कहते हैं कि एक व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट रख सकता है, चाहे वह किसी बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में। PPF योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक दीर्घकालिक बचत योजना है, जिसका मकसद लोगों को सुरक्षित निवेश के साथ टैक्स लाभ देना है। वर्तमान नियमों के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक अपने नाम पर सिर्फ एक PPF खाता खोल सकता है। यह खाता 15 साल की अवधि के लिए होता है और इसमें हर साल न्यूनतम 500 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।

कई लोग इस सीमा को बढ़ाने के लिए अलग-अलग संस्थानों में नया खाता खोल लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी ने पहले से किसी बैंक में PPF अकाउंट खोला है और बाद में पोस्ट ऑफिस या किसी दूसरे बैंक में दूसरा अकाउंट खोल लिया, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। कई बार ऐसा जानकारी के अभाव में भी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि PPF में 1.5 लाख रुपये की निवेश सीमा सभी खातों को मिलाकर लागू होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर खाते में अलग-अलग 1.5 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अतिरिक्त जमा राशि पर ब्याज का लाभ नहीं मिलेगा और टैक्स छूट भी प्रभावित हो सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज्यादा PPF खाते पाए जाते हैं, तो सरकार या संबंधित बैंक उन्हें "डुप्लिकेट अकाउंट" मान सकता है। ऐसे मामलों में आमतौर पर एक खाते को वैध माना जाता है और बाकी खातों को बंद कर दिया जाता है। सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि दूसरे या अतिरिक्त खाते में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज रद्द किया जा सकता है। यानी आपने जितना पैसा जमा किया, वह तो वापस मिल सकता है, लेकिन उस पर कमाया गया ब्याज हाथ से निकल सकता है। यह नुकसान छोटा नहीं होता।

रोज सनस्क्रीन लगाने के बाद भी टैनिंग की हो रही दिक्कत? डर्माटोलॉजिस्ट से जानें वजह

हेल्थ डेस्क। धूप से त्वचा को बचाने के लिए सनस्क्रीन को सबसे प्रभावी उपायों में गिना जाता है। इसके बावजूद कई लोग शिकायत करते हैं कि वे रोज सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर भी उनकी त्वचा टैन हो जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो संभव है कि समस्या सनस्क्रीन में नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल के तरीके में हो। त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार, केवल सनस्क्रीन लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। सही SPF, सही मात्रा और सही समय पर दोबारा लगाना भी उतना ही जरूरी है।

1. पर्याप्त मात्रा में सनस्क्रीन नहीं लगाना

अधिकांश लोग चेहरे पर जरूरत से कम सनस्क्रीन लगाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चेहरे और गर्दन के लिए लगभग दो उंगलियों जितनी मात्रा में सनस्क्रीन लगानी चाहिए। कम मात्रा लगाने से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती।

2. बार-बार दोबारा नहीं लगाना

एक बार सुबह सनस्क्रीन लगाने से पूरे दिन सुरक्षा नहीं मिलती।

हर 2 से 3 घंटे में दोबारा लगाना चाहिए। यदि पसीना ज्यादा आता है या आप बाहर हैं, तो री-एप्लाई करना और भी जरूरी हो जाता है।

3. SPF कम होना-यदि आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं, तो SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनना बेहतर माना जाता है। SPF 15 दैनिक हल्के उपयोग के लिए पर्याप्त हो सकता है। तेज धूप में SPF 30 या SPF 50 अधिक प्रभावी सुरक्षा देता है।

4. केवल सनस्क्रीन पर निर्भर रहना-सनस्क्रीन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 100% सुरक्षा नहीं देता। टैनिंग से बचने के लिए:

टोपी या कैप पहनें।

धूप का चश्मा लगाएं।

छाता इस्तेमाल करें।

दोपहर 11 बजे से 4 बजे के बीच तेज धूप में कम निकलें।

5. पानी या पसीने से सनस्क्रीन हट जाना-मानसून और गर्मियों में पसीना अधिक आने से सनस्क्रीन की परत कमजोर हो सकती है।

यदि आपः जिम जाते हैं, तैराकी करते हैं, या ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो वाटर-रेसिस्टेंट सनस्क्रीन का उपयोग करें।

6. UV किरणें केवल धूप में ही नहीं होतीं-कई लोग सोचते हैं कि बादल होने पर सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती, जबकि UV किरणें बादलों के बीच से भी त्वचा तक पहुंच सकती हैं। यही कारण है कि बरसात और सर्दियों में भी टैनिंग हो सकती है।

7. कुछ दवाएं और स्किन कंडीशन भी हो सकती हैं जिम्मेदार-कुछ दवाएं त्वचा को सूरज की रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती हैं। इसके अलावा हार्मोनल बदलाव, मेलाज्मा या हाइपरपिग्मेंटेशन जैसी समस्याओं के कारण भी त्वचा जल्दी टैन हो सकती है। डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह

ब्रॉड-स्पेक्ट्रम SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन चुनें। बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले लगाएं।

गड़े खजाने की तलाश में 21 हत्याओं की साजिश!

कब्रों से निकाले गए शव, फॉरेंसिक जांच से खुलेगा रहस्य

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले से एक बेहद सनसनीखेज और भयावह मामला सामने आया है। जिले के पुराना खर्वे गांव में कथित तौर पर गड़े खजाने की खोज और तांत्रिक अनुष्ठानों के नाम पर 21 लोगों की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने व्यापक जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान अधिकारियों ने संदेह के आधार पर कई कब्रों को खुदवाकर शव बाहर निकलवाए हैं। इन शवों का पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक परीक्षण कराया जा रहा है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोगों की मौत सामान्य नहीं थी और उनके पीछे किसी संगठित साजिश का हाथ हो सकता है।

सूत्रों के अनुसार, मामले का संबंध कथित तांत्रिक गतिविधियों और गड़े हुए खजाने की तलाश से जोड़ा जा रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या लोगों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर अपराध को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो सक्रिय नहीं था। प्रशासन ने पूरे मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए विशेषज्ञ फॉरेंसिक टीमों की मदद ली है। शवों से प्राप्त नमूनों की वैज्ञानिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौतें किन परिस्थितियों में हुईं और क्या उनमें किसी आपराधिक साजिश के संकेत मौजूद हैं। गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस खुलासे के बाद भय और चर्चा का माहौल है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है तथा पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि आरोप सही साबित हुए तो यह राज्य के सबसे बड़े आपराधिक और अंधविश्वास से जुड़े मामलों में से एक हो सकता है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने तथा जांच में सहयोग करने की अपील की है। अब पूरे मामले की सच्चाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।

कांग्रेस में अनुशासन पर सवाल

जीतू पटवारी के आह्वान को 21 जिलों में नहीं मिला साथ, NSUI पदाधिकारियों को नोटिस

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी असंतोष एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता के नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया गया था, लेकिन कई जिलों में यह कार्यक्रम अपेक्षित स्तर पर नहीं हो सका। इस घटनाक्रम के बाद पार्टी संगठन ने सख्त रुख अपनाते हुए एनएसयूआई

पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला इकाइयों और छात्र संगठन एनएसयूआई को विरोध प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी के निर्देश दिए थे। हालांकि 21 जिलों में प्रदर्शन या तो नहीं हुए या फिर बेहद कमजोर रहे। इससे संगठन के भीतर समन्वय और अनुशासन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि जब प्रदेश स्तर पर कोई आंदोलन घोषित किया जाता है तो सभी अनुषांगिक संगठनों और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वे उसे सफल बनाएं। प्रदर्शन में अपेक्षित भागीदारी नहीं मिलने को संगठनात्मक निर्देशों की अवहेलना के रूप में देखा जा रहा है।

इसी के चलते कांग्रेस ने संबंधित जिलों के एनएसयूआई पदाधिकारियों और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से जवाब तलब किया है। नोटिस में पूछा गया है कि निर्देशों के बावजूद प्रदर्शन क्यों नहीं हुए और संगठनात्मक कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता क्यों दिखाई गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के भीतर संगठनात्मक एकजुटता की परीक्षा भी बन गया है। आगामी चुनावी चुनौतियों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व किसी भी तरह की ढिलाई या गुटबाजी को लेकर सख्त संदेश देना चाहता है। वहीं कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि कई जिलों में स्थानीय कारणों और संगठनात्मक व्यस्तताओं की वजह से कार्यक्रम पूरी तरह सफल नहीं हो सके। हालांकि अंतिम निर्णय नोटिस के जवाब मिलने के बाद ही लिया जाएगा। इस घटनाक्रम ने प्रदेश कांग्रेस में अनुशासन, संगठनात्मक सक्रियता और नेतृत्व की पकड़ को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि नोटिस प्राप्त पदाधिकारी क्या जवाब देते हैं और पार्टी नेतृत्व आगे क्या कार्रवाई करता है।

भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच

ग्वालियर CMHO पर गिरी गाज: डॉ. सचिन श्रीवास्तव पद से हटाए गए

ग्वालियर। ग्वालियर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) रहे को पद से हटा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग की अपर सचिव द्वारा जारी आदेश के बाद स्वास्थ्य महकमे में हलचल तेज हो गई है। डॉ. सचिन श्रीवास्तव पिछले कुछ समय से विभिन्न विवादों और आरोपों को लेकर चर्चा में थे। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों को लेकर कई बार शिकायतें भी सामने आई थीं, जिसके बाद विभागीय स्तर पर मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था।

सूत्रों के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त शिकायतों और प्रशासनिक रिपोर्टों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि विभाग की ओर से जारी आदेश में विस्तृत कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे हाल के विवादों से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले को प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है। ग्वालियर में लंबे समय से CMHO कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे थे। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और सामाजिक संगठनों ने भी समय-समय पर जांच की मांग की थी। डॉ. श्रीवास्तव को हटाए जाने के बाद अब नए अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा और व्यवस्थाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी। इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य महकमे में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि विभाग अब अन्य लंबित शिकायतों और विवादित मामलों की भी समीक्षा कर सकता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे विभागीय जांच और प्रशासनिक कार्रवाई किस दिशा में बढ़ती है।

पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी. से ईडी की 9 घंटे पूछताछ

कोच्चि। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी से बुधवार को नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। यह पूछताछ उनकी बंद हो चुकी आईटी कंपनी और खनन क्षेत्र की कंपनी सीएमआरएल (Cochin Minerals and Rutile Limited) के बीच कथित वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामले में की गई। सूत्रों के अनुसार, वीणा टी. ईडी के समक्ष निर्धारित समय पर पेश हुईं, जहां अधिकारियों ने उनसे कंपनी के कारोबारी लेनदेन, परामर्श सेवाओं और वित्तीय दस्तावेजों को लेकर विस्तृत सवाल-जवाब किए।

जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संबंधित कंपनियों के बीच हुए भुगतान और समझौतों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के तत्व मौजूद थे या नहीं।

मामला उस समय चर्चा में आया था जब आरोप लगे थे कि वीणा की कंपनी को सीएमआरएल से नियमित भुगतान प्राप्त हुआ, जबकि उसके बदले में सेवाएं प्रदान किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए। इन आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हुआ था और विपक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। हालांकि, वीणा टी. और उनसे जुड़े पक्ष पहले भी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उनका कहना है कि सभी व्यावसायिक लेनदेन वैध और कानूनी प्रक्रिया के तहत हुए थे तथा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई। ईडी अब पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी, दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही है। जांच एजेंसी आगे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अन्य व्यक्तियों से भी पूछताछ कर सकती है।

'जहांगीर से लेकर अभिजीत तक' TMC नेताओं की पुलिस परेड पर हाईकोर्ट सख्त, पूछा-क्या यही कानून का राज है?

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की पुलिस द्वारा सार्वजनिक रूप से परेड कराए जाने के मामले में ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से सवाल किया कि क्या किसी आरोपी को इस तरह सरेआम घुमाना "कानून के शासन" (Rule of Law) के अनुरूप है। मामला उन तस्वीरों और वीडियो के सामने आने के बाद उठा, जिनमें टीएमसी से जुड़े नेताओं—जहांगीर खान, गुड्डू अंसारी, आकाश सिंह और अभिजीत समेत अन्य आरोपियों को पुलिस सुरक्षा के बीच सार्वजनिक रूप से ले जाते हुए देखा गया। इन दृश्यों को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस तेज हो गई है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगना और उसका दोषी सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। अदालत ने पूछा कि क्या जांच एजेंसियों को कानून के दायरे में रहकर काम नहीं करना चाहिए और क्या सार्वजनिक परेड से आरोपियों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होते? अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए पूछा कि आरोपियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके लिए कौन-से कानूनी प्रावधानों का पालन किया गया। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि क्या इस कार्रवाई के लिए कोई स्पष्ट प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था।

विपक्षी दलों ने मामले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। वहीं सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और जांच एजेंसियां निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रही हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के संविधान में प्रत्येक आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई और गरिमा के साथ व्यवहार का अधिकार प्राप्त है। ऐसे मामलों में अदालतें पहले भी पुलिस और जांच एजेंसियों को यह याद दिलाती रही हैं कि किसी व्यक्ति को दोषी साबित होने से पहले अपराधी की तरह सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करना न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत माना जा सकता है।

वायुसेना अधिकारी की पत्नी को कथित धर्मांतरण के जाल में फंसाने वाला मौलाना गिरफ्तार, अब खुलेंगी पूरे नेटवर्क की परतें

नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी से कथित दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहा तीसरा आरोपी मौलाना मकसूद महमूद मकसूद आखिरकार पुलिस के सामने पेश हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

इस गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस अब पूरे मामले की तह तक पहुंचने और कथित नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पहले उससे संपर्क स्थापित किया और फिर उसे कथित रूप से अपने प्रभाव में लेकर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया। शिकायत में दावा किया गया है कि आरोपियों ने विश्वास जीतने के बाद महिला को एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने जाल में फंसाया। बाद में उसके आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें तैयार कर ब्लैकमेल किया गया तथा उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूले गए।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उस पर धर्म परिवर्तन के लिए लगातार दबाव बनाया गया। कथित तौर पर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल कर उससे कुछ धार्मिक घोषणाएं भी कराई गईं। महिला का आरोप है कि यह सब उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, वसूली, धोखाधड़ी, जबरन धर्मांतरण और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपियों में शामिल अय्याज ताज मदारे और उसका सहयोगी अमीन शेख पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं तीसरा आरोपी मौलाना मकसूद घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी।

बढ़ते दबाव और संभावित गिरफ्तारी की आशंका के बीच उसने सोनेगांव थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

सूत्रों का कहना है कि जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या यह मामला केवल एक महिला तक सीमित था या फिर इसी तरह के अन्य मामले भी सामने आ सकते हैं। पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, बैंक खातों, सोशल मीडिया संपर्कों और कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि कथित तौर पर वसूली गई रकम कहां-कहां खर्च की गई और क्या इसमें अन्य लोगों की भी भूमिका थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारी खुलकर ज्यादा जानकारी देने से बच रहे हैं, लेकिन जांच टीम का मानना है कि मौलाना से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। पुलिस अदालत से रिमांड मांगकर आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ भी कर सकती है ताकि कथित नेटवर्क और उसकी कार्यप्रणाली को समझा जा सके।

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पीड़िता एक वायुसेना अधिकारी की पत्नी बताई जा रही है। हालांकि सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से पुलिस ने पीड़िता तथा उसके परिवार की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। जांच एजेंसियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है और अदालत में आरोप सिद्ध होने तक सभी आरोपियों को कानूनन आरोपी ही माना जाएगा, दोषी नहीं।

अब भारत के मंदिरों को कौन लूट रहा है?

धर्म, धंधा और सरकार के बीच फंसी आस्था

राजेश धाकड़

कभी भारत के मंदिरों को लूटने के लिए विदेशी आक्रमणकारी आते थे। इतिहास में हमें बताया गया कि महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी, मुगल शासक और अंग्रेज भारत की संपदा पर नजर रखते थे। उस समय लुटेरा पहचान में आ जाता था। उसके हाथ में तलवार होती थी, सेना होती थी और इरादे भी स्पष्ट होते थे। लेकिन आज भारत स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कानून है, न्यायपालिका है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े विशाल मंदिर हैं। फिर भी समय-समय पर मंदिरों के दान, संपत्ति और प्रबंधन को लेकर सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर आज मंदिरों को नुकसान पहुंचाने वाला कौन है? आज कोई सेना लेकर मंदिरों पर हमला नहीं करता। यदि कहीं लूट होती है तो वह फाइलों, खातों, प्रबंधन और अपारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से होती है। आम श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई से दान करता है। वह विश्वास करता है कि उसका योगदान धर्म, सेवा और समाजहित में उपयोग होगा। लेकिन जब दान राशि, आभूषणों या संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विवाद सामने आते हैं, तब सबसे अधिक आहत वही श्रद्धालु होता है जिसने भगवान के प्रति विश्वास के कारण अपना योगदान दिया था।

विडंबना यह है कि भगवान ने कभी वैभव की मांग नहीं की। भगवान राम ने वनवास का जीवन जिया, भगवान कृष्ण ग्वाल-बालों के बीच रहे और भगवान शिव को वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। फिर भी उनके नाम पर अरबों रुपये की संपत्तियां और विशाल व्यवस्थाएं खड़ी हो गईं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पीछे रह गए हैं और उनके नाम पर चलने वाली व्यवस्थाएं आगे निकल गई हैं। समस्या धर्म में नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर खड़ी होने वाली अपारदर्शी व्यवस्थाओं में है। यदि किसी पंचायत, नगर निगम या सरकारी विभाग के खर्च का हिसाब मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है, तो धार्मिक संस्थाओं के करोड़ों-अरबों रुपये के दान का लेखा-जोखा मांगना गलत कैसे हो सकता है?

दुर्भाग्य से हमारे समाज में कई बार प्रबंधन पर सवाल उठाने को धर्म पर हमला मान लिया जाता है। जबकि मंदिर और उसका प्रबंधन दो अलग-अलग विषय हैं। भगवान और उनके नाम पर चल रही संस्था एक नहीं हैं। आस्था का सम्मान करते हुए व्यवस्था से जवाब मांगना लोकतांत्रिक और नैतिक दोनों दृष्टि से उचित है। आज धर्म और धार्मिक कारोबार के बीच की दूरी भी लगातार कम होती दिखाई देती है। वीआईपी दर्शन, विशेष पूजा, महंगे टिकट और सुविधाओं के नाम पर बढ़ती व्यावसायिकता यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं भक्त श्रद्धालु से ग्राहक तो नहीं बनता जा रहा। अंधभक्ति का सबसे बड़ा खतरा यही है कि वह सवाल पूछने की क्षमता को समाप्त कर देती है। इतिहास गवाह है कि जब किसी भी संस्था में जवाबदेही समाप्त होती है, तब भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही सिद्धांत धार्मिक संस्थाओं पर भी लागू होता है। धर्म का सबसे बड़ा मित्र पारदर्शिता है और सबसे बड़ा शत्रु अपारदर्शिता। जो संस्था ईमानदार है, उसे अपने आय-व्यय का विवरण सार्वजनिक करने में कोई भय नहीं होना चाहिए। मंदिर किसी व्यक्ति या समूह की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सामूहिक आस्था के केंद्र हैं।

आवश्यकता किसी धर्म के विरोध की नहीं है। आवश्यकता है कि सभी धार्मिक संस्थाओं में पारदर्शी प्रबंधन, स्वतंत्र ऑडिट, सार्वजनिक लेखा-जोखा और जवाबदेही सुनिश्चित हो। इससे धर्म कमजोर नहीं होगा, बल्कि लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। क्योंकि मंदिरों को सबसे बड़ा खतरा आलोचकों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होता है जो आस्था को अवसर और श्रद्धा को कारोबार में बदल देते हैं। ऐसे लोग तलवार लेकर नहीं आते, वे धर्म की भाषा बोलते हुए व्यवस्था के भीतर प्रवेश करते हैं। और जब ऐसा होता है तो नुकसान केवल धन का नहीं, बल्कि विश्वास का होता है। आज प्रश्न इतिहास के आक्रमणकारियों का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी आस्था को इतना जागरूक बना पाए हैं कि धर्म के नाम पर खड़े हर तंत्र से जवाब मांग सकें? यदि नहीं, तो इतिहास और वर्तमान की लूट में अंतर केवल तरीका बदलने का है, पीड़ा का नहीं।

72 साल पुराने शास्त्री ब्रिज का होगा कायाकल्प,

Indore। शहर के सबसे अहम और ऐतिहासिक पुलों में शामिल Shastri Bridge अब पूरी तरह नए स्वरूप में नजर आएगा। वर्ष 1953 में लोकार्पित इस 72 साल पुराने ब्रिज का पुनर्निर्माण तय हो गया है। भारतीय रेलवे ने इसके लिए 139 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। हालांकि पहले इसे 6 लेन में बनाने की योजना थी, लेकिन जगह की कमी के कारण रेलवे ने फिलहाल 4 लेन के नए ब्रिज को ही स्वीकृति दी है। नया शास्त्री ब्रिज मौजूदा पुल की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा चौड़ा, 30 मीटर अधिक लंबा और 2.7 मीटर ऊंचा बनाया जाएगा। इससे जहां यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है, वहीं शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच आवागमन भी अधिक सुगम हो सकेगा। यह ब्रिज इंदौर के ट्रैफिक सिस्टम की रीढ़ माना जाता है। पलासिया, एमजी रोड, रीगल, एमटीएच कंपाउंड और राजबाड़ा जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर दिन हजारों वाहन इस पुल से गुजरते हैं, जिससे इस पर दबाव लगातार बढ़ता गया है। यही वजह है कि लंबे समय से इसके पुनर्निर्माण की मांग उठ रही थी।

रेलवे के अनुसार नया ब्रिज कुल 438 मीटर लंबा होगा, जबकि मौजूदा ब्रिज की लंबाई 400

मीटर है। इसकी ऊंचाई वर्तमान 4.7 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर की जाएगी, ताकि बड़े वाहनों और रेल संचालन के लिहाज से अधिक सुविधा मिल सके। इसके अलावा नया पुल ऊंट की पीठ यानी आर्चनुमा डिजाइन में तैयार किया जाएगा, जिससे इसकी मजबूती और आकर्षण दोनों बढ़ेंगे। ब्रिज के नीचे दोनों ओर 6-6 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। साथ ही जल निकासी की आधुनिक व्यवस्था, नई सीवर लाइन, दोनों तरफ फुटपाथ और बेहतर विद्युत व्यवस्था का भी निर्माण किया जाएगा। इससे आसपास के क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। शास्त्री ब्रिज का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसका उद्घाटन 12 जनवरी 1953 को तत्कालीन परिवहन मंत्री Lal Bahadur Shastri ने किया था और उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया। तब से लेकर अब तक यह पुल इंदौर की यातायात व्यवस्था का अहम हिस्सा बना हुआ है।

हालांकि इस पुनर्निर्माण के साथ शहर के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन कैसे होगा। क्योंकि यह पुल बंद होने की स्थिति में पूरा दबाव Patel Bridge पर आएगा, जो पहले से ही भारी ट्रैफिक झेल रहा है। इसके अलावा आरएनटी मार्ग को ऊंचा करने और रीगल रोटरी क्षेत्र में भी कुछ निर्माण कार्य प्रभावित हो सकते हैं। नगर निगम की हालिया जांच में यह भी सामने आया था कि पुराने ब्रिज को चूहों ने भी नुकसान पहुंचाया है। कई हिस्सों में बिल बनने और संरचना कमजोर होने के कारण मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे। फिलहाल रेलवे द्वारा सर्वे, डिजाइन और ड्राइंग तैयार की जाएगी, जिसमें कुछ समय लगेगा। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लगभग 6 महीने लग सकते हैं। टेंडर मंजूर होने और वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद 15 महीने में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इंदौर को जल्द ही एक आधुनिक, मजबूत और अधिक क्षमता वाला नया शास्त्री ब्रिज मिलने वाला है। हालांकि काम शुरू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन यह साफ है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में यह परियोजना बड़ा बदलाव लाने वाली है।

नामांतरण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव

इंदौर। इंदौर नगर निगम (Municipal Corporation) में संपत्तियों (property) का नामांतरण (mutation) करने के लिए चल रही व्यवस्था में बड़े परिवर्तन किए गए हैं। नए परिवर्तन के अनुसार अब संपत्ति का मौके पर सर्वे भी किया जाएगा और सभी संबंधित पक्षों के नाम पर नोटिस भी जारी किए जाएंगे। नामांतरण के लिए रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति को भी अनिवार्य किया गया है।फर्जी दस्तावेजों से महालक्ष्मी नगर में संपत्ति का नामांतरण किए जाने का मामला पिछले दिनों उजागर हुआ था। इस मामले में जोनल कार्यालय के सहायक राजस्व अधिकारी और निगम के ही एक अन्य कर्मचारी को निलंबित किया गया है। इस मामले के उजागर होने के पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस स्थिति को देखते हुए निगम के राजस्व विभाग के अपर आयुक्त आकाश सिंह द्वारा नामांतरण की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों से नामांतरण पर रोक लगेगी, वहीं नकली काम करने वाले सीधे-सीधे आपराधिक धाराओं में फंस सकते हैं। संपत्ति खरीदने पर जहां खरीदार और बेचवाल का आधार कार्ड आवेदन साथ अनिवार्य किया गया है, वहीं रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी, जाहिर सूचना आदि को अनिवार्य किया गया है। नामांतरण के लिए आवेदन केवल दावेदार या उसके द्वारा नियुक्त किया गया वकील ही वकालतनामा देकर करवा सकेंगे। इस नई व्यवस्था में वारिस नाते होने वाले नामांतरण में भी यही प्रक्रिया रहेगी।